छत्तीसगढ़ की तृतीय विधान सभा
तृतीय सत्र

श्री ई.एस.एल. नरसिम्हन

राज्यपाल, छत्तीसगढ़

का

अभिभाषण

दिनांक 11 जनवरी, 2010

माननीय सदस्यगण,

नववर्ष 2010 में छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस प्रथम अधिवेशन के अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। छत्तीसगढ़ के पहले दशक को स्वर्णाक्षरों में दर्ज करने के लिए आप सभी लोगों ने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसके लिए आप सभी को बधाईयां तथा नए वर्ष में नया योगदान जोड़ने के लिए शुभकामनाएं देता हूं।

2. राज्य में चुनावों का दौर लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों में चुनाव कार्य संपन्न कराना अपने आप में काफी कठिन और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी निबाहने में लगे उन हजारों अधिकारियों , कर्मचारियों, पुलिस तथा सुरक्षा बलों के जवानों के साथ मतदाताओं को भी मैं साधुवाद देता हूं, जिन्होंने इस पावन कर्त्तव्य के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपनी भागीदारी निभाई है।

3. मेरी सरकार द्वारा किसानों के लिए लागू की गई योजनाओं के नतीजे उत्साहजनक रहे हैं। राज्य गठन के समय लाभकारी फसलों का रकबा लगभग तिरपन लाख हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर लगभग पैंसठ लाख हेक्टेयर हो गया है। अनाज, दलहन और तिलहन फसलों का कुल उत्पादन लगभग अन्ठावन लाख मीट्रिक टन से बढ़कर तिहत्तर लाख मीट्रिक टन हो गया है। उद्यानिकी, मछली पालन तथा पशुधन विकास की योजनाओं से भी आशातीत सफलता मिली है।

4. किसानों को सिंचाई साधनों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के अभियान के तहत शाकम्बरी योजना में इकतीस हजार से अधिक लघु–सीमांत सब्जी उत्पादक किसानों को अनुदान दिया गया है। किसान समृद्धि योजना का दायरा वृष्टि छाया क्षेत्रों से बढ़ाकर एक सौ दस विकासखण्डों तक किया जा चुका है।

5. मेरी सरकार देश में सबसे किफायती दर पर कृषि ऋण देने के संकल्प में खरी उतरी है। मात्र तीन प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने से किसानों की डिफाल्टर होने की मजबूरी खत्म हुई है। इस साल उन्हें करीब तेरह सौ करोड़ रूपये का ऋण उपलब्ध कराने का इंतजाम किया गया है। यह किफायती दर गौ–पालन, मछली पालन तथा उद्यानिकी के लिए भी लागू की गई है।

6. लघु एवं सीमांत किसानों को प्रमाणिक बीज के उपयोग की सुविधा देने के लिए 'अक्ती बीज संवर्धन' योजना लागू की गई है। गन्ना किसानों को उपज का बेहतर दाम दिलाने और उनके हितों का ध्यान रखकर मेरी सरकार द्वारा सहकारी क्षेत्र में राज्य का दूसरा शक्कर कारखाना बालोद में स्थापित कर दिया गया है। तीसरे शक्कर कारखाने की स्थापना का कार्य अंबिकापुर में शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा।

7. मेरी सरकार ने किसानों का एक–एक दाना धान खरीदने का वायदा निभाया और विगत वर्ष सैंतीस लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीद कर एक कीर्तिमान बनाया है। इस वर्ष भी धान खरीदी और भुगतान की प्रक्रिया जारी है। राज्य सरकार द्वारा इस साल किसानों को बोनस के रूप में लगभग दो सौ करोड़ रूपए दिए जाएंगे।

8. अल्पकालीन कृषि साख संरचना को मजबूत करने के लिए मेरी सरकार ने वैद्यनाथन कमेटी की अनुशंसा के अनुरूप गत वर्ष इकतीस करोड़ रूपये से अधिक राशि दी थी, लगभग इतनी ही राशि इस वर्ष भी दी जाएगी। इस अंशदान से राज्य सहकारी बैंक, छह जिला सहकारी बैंक, एक हजार से अधिक प्राथमिक समितियों को पांच सौ बयासी करोड़ रूपये के आर्थिक पैकेज का लाभ सुनिश्चित होगा।

9. राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखे पेट सोने को मजबूर नहीं होगा–मेरी सरकार ने काफी दृढ़ता से इस घोषणा को अमलीजामा पहनाया है। अंत्योदय परिवारों को एक रूपये किलो में और अन्य गरीब परिवारों को दो रूप्ये प्रति किलो में प्रतिमाह पैंतीस किलो चावल देने की योजना जुलाई, 2009 से प्रारंभ कर दी गई है। 'छत्तीसगढ़ अमृत नमक' योजना का दायरा भी बढ़ाकर, अब हर गरीब परिवार को प्रतिमाह दो किलो आयोडाइज्ड नमक निःशुल्क दिया जा रहा है। इस तरह लगभग सैंतीस लाख परिवारों को स्वावलम्बन और विश्वास की नई रौशनी मिली है।

10. मेरी सरकार ने आर्थिक तकलीफों से जूझ रहे साहित्यकारों एवं कलाकारों के लिए मासिक सहायता–राशि को सात सौ रूपये से बढ़ाकर पन्द्रह सौ रूपये प्रतिमाह कर दिया है। कलाकार कल्याण कोष से जरूरतमंद कलाकारों एवं साहित्यकारों को मिलने वाली राशि भी पांच हजार रूपये से बढ़ाकर पन्द्रह हजार रूपए कर दी गई है।

11. मेरी सरकार ने भूमिहीनों तथा गरीबों के सिर पर छत मुहैया कराने के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। भूमिहीन ग्रामीण परिवारों को भूमि का पट्टा दिया जा रहा है। दीनदयाल आवास योजना, डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी आवास योजना, अटल आवास योजना के तहत गरीबों को काफी रियायती दरों पर तथा विशेष पिछड़ी जनजातियों के करीब आठ हजार परिवारों को निःशुल्क पक्के आवास बनाकर दिए जा रहे हैं।

12. मेरी सरकार द्वारा महिला स्व–सहायता समूहों को आर्थिक स्वावलम्बन के लिए मदद देने की कड़ी में, उन्हें आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए 'रेडी–टू–ईट' पोषण आहार के निर्माण और प्रदाय का कार्य भी सौंपा जा रहा है। आंगनबाड़ी केन्द्रों में दर्ज अत्यधिक कुपोषित बच्चों के शासकीय खर्च पर इलाज के लिए 'मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना' लागू की गई है। निःशक्त बच्चों के उपचार हेतु साढ़े चार करोड़ रूपए की लागत से सेरेब्रेल पाल्सी गेट लेब की स्थापना की गई है।

13. बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मेरी सरकार द्वारा जगदलपुर और बीजापुर विकासखण्ड में 'धनलक्ष्मी योजना' संचालित की जा रही है। विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के आर्थिक स्वावलम्बन के लिए बस्तर, दक्षिण बस्तर, बीजापुर और नारायणपुर जिले में 'शक्ति स्वरूपा योजना' प्रारंभ की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निःशुल्क सायकल देने का संकल्प भी पूरा किया जा रहा है।

14. मेरी सरकार ने वन में बेहतर जीवन की नई संभावनाओं को तलाशा और तराशा है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ को देश का अव्वल राज्य बनने का गौरव मिला है। इस अधिनियम के तहत पात्र वन निवासियों को सर्वाधिक संख्या में वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किए गए हैं।

15. मेरी सरकार, वनोपज के सहारे जीवन–यापन करने वाले लोगों को आमदनी बढ़ाने के अधिकाधिक साधन प्रदान कर रही है। तेंदूपत्ता संग्राहकों को विगत एक वर्ष में पारिश्रमिक के रूप में पनचानबे करोड़ रूपए तथा बोनस के रूप में सढ़सठ करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। विगत वर्ष साल बीज संग्राहकों को अठासी करोड़ रूपए का भुगतान किया गया। तेरह लाख से अधिक महिला तेन्दूपत्ता संग्राहकों को निःशुल्क चरणपादुका दी जा रही है। चार सौ पच्चीस वन ग्रामों के विकास के लिए लगभग पनचानबे करोड़ रूपए की लागत से अधोसंरचना विकास का कार्य किया जा रहा है।

16. मेरी सरकार के विशेष प्रयासों से प्रदेश को कैम्पाफण्ड के लिए इस वर्ष एक सौ तेईस करोड़ रूपए की राशि मिली है। जिससे क्षतिपूरक वनीकरण सहित वन विकास से संबंधित विभिन्न कार्य किए जाएंगे। राज्य में बांस वनों का उत्पादन बढ़ाने और इन्हें स्थानीय आबादी की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन बनाने के लिए सत्ताइस बांस प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना की जा रही है।

17. मेरी सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को बेहतर शिक्षा और बेहतर रोजगार के माध्यम से विकास की मुख्यधारा में लाने की रणनीति अपनाई है। 'मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना', 'जवाहर उत्कर्ष योजना', 'छात्रावास–एवं आश्रम योजना','विशेष शिक्षण केन्द्र योजना', 'कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना' जैसे अनेक उपायों से इन वर्गों में शिक्षा के प्रति ललक बढ़ाई जा रही है। यह हर्ष का विषय है कि अनुसूचित जनजाति की जिन पच्चीस युवतियों को एयर होस्टेस का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया, उसमें से दस युवतियों को रोजगार प्राप्त हो चुका है। इसी तरह पायलट प्रशिक्षण योजना के एक हितग्राही को कमर्शियल पायलट का लायसेंस भी मिल चुका है। वाहन चालक प्रशिक्षण योजना, नर्सिंग पाठ्यक्रम योजना के माध्यम से युवक एवं युवतियों को रोजगारपरक शिक्षा दी जा रही है।

18. शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में मेरी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। इस वर्ष छह से चौदह आयु वर्ग के चौरासी हजार अप्रवेशी और करीब पचास हजार शाला त्यागी बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ा गया है। दूरवर्ती शिक्षा में एड्यूसेट के उपयोग हेतु पचास सेटेलाईट टर्मिनल लगाए जा चुके हैं। प्रौढ़ एवं पढ़ाई छोड़ चुके सात लाख लोगों को पांचवीं एवं आठवीं परीक्षा में उत्तीर्ण होना देश में एक कीर्तिमान बना है। राज्य में हर पांच किलोमीटर पर हाईस्कूल खोले जाएंगे। हाईस्कूल–हायर सेकेण्डरी के सभी बच्चों को परीक्षा केन्द्रों में फर्नीचर उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी शीघ्र पूरा किया जाएगा। शिक्षाकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया को सुगम तथा पारदर्शी बनया गया है। लगभग चालीस हजार शिक्षाकर्मियों की भर्ती से शालाओं में शिक्षकों की कमी दूर करने में मदद मिली है।

19. मेरी सरकार के प्रयासों से वर्ष 2003 में चिन्हांकित की गई बसाहटों में से निन्यानबे प्रतिशत में शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा चुका है। शेष बची सरगुजा, जशपुर एवं दंतेवाड़ा जिले की चवालीस बसाहटों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने की कार्यवाही भी शीघ्र पूरी कर ली जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना भी की गई है। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अमल की कारगर रणनीति से तेरह लाख छत्तीस हजार परिवारों के लिए व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय का निर्माण करा दिया गया है। इन्कयानबे प्रतिशत शालाओं तथा पचहत्तर प्रतिशत आंगनबाड़ियों में शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। छत्तीसगढ़ की शत–प्रतिशत आंगनबाड़ियों और शालाओं में शौचालय निर्माण शीघ्र पूर्ण करने का लक्ष्य है।

20. मेरी सरकार के प्रयासों से स्वास्थ्य अधोसंरचना को राष्ट्रीय औसत के समकक्ष लाया गया है। अट्ठारह जिला अस्पताल, एक सौ छत्तीस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सात सौ इक्कीस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं चार हजार सात सौ इकचालीस उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जा चुके हैं। राज्य का चौथा मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में खोलने का कार्य प्रगति पर है। 'छत्तीसगढ़ रूरल मेडिकल कोर' की स्थापना की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सालयों को कठिन और कठिनतम भागों में बांटकर चिकित्सकों को प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था की गई है। दूरस्थ क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तीन सौ से अधिक 'ग्रामीण चिकित्सा सहायकों' को पदस्थ किया गया है।

21. मेरी सरकार ने चिकित्सा प्रणालियों के समन्वय से जनसुविधाओं का दायरा बढ़ाने के लिए एक सौ इक्कीस आयुर्वेद ग्रामों का विकास किया है। आठ आदिवासी बहुल जिलों के सामुदायिक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में करीब चार सौ आयुष चिकित्सकों के पदों का सृजन किया गया है। एलोपैथी के साथ आयुर्वेद चिकित्सा सुविधा देने के लिये पन्द्रह जिला चिकित्सालयों में आयुष विंग की स्थापना की गई है। विभिन्न प्रयासों से अस्सी प्रतिशत से ज्यादा शिशु स्वास्थ्य सूचकांक अब राष्ट्रीय औसत से बेहतर हो गये हैं। 'मुख्यमंत्री बाल हृदय संरक्षण योजना' की अभिनव पहल से आठ सौ से अधिक बच्चों के हृदय का ऑपरेशन कर उन्हें नया जीवन प्रदान किया गया है। बीपीएल परिवारों को एक वर्ष में तीस हजार रूपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की कारगर व्यवस्था के लिए स्मार्ट कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस योजना के पहले चरण में छब्बीस लाख गरीब परिवार लाभान्वित होंगे।

22. राज्य की सिंचाई क्षमता वर्तमान में लगभग इकतीस प्रतिशत है। इसे बढ़ाकर राष्ट्रीय स्तर के बराबर उन्चास प्रतिशत तक करने के लिए मेरी सरकार प्रयासरत है। छह वृहद, बत्तीस मध्यम और बाईस सौ से अधिक लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। पांच वृहद, सात मध्यम और चार सौ पचास से अधिक लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य जारी है। इस वर्ष अस्सी हजार हेक्टेयर रकबे में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार का लक्ष्य है।

23. मेरी सरकार ने बड़े बांधों से आने वाली समस्याओं से बचने और भू–जल स्तर बढ़ाने के लिए नदियों में करीब छह सौ एनीकटों के निर्माण का लक्ष्य रखा है, जिसके विरूद्ध एक सौ चार एनीकटों का निर्माण किया जा चुका है तथा एक सौ दस एनीकट निर्माणाधीन हैं। नदी कछारों का एकीकृत मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इससे जल संसाधनों का समन्वित विकास और अधिक तेजी से किया जा सकेगा। सिंचाई कर की बकाया राशि का पचास प्रतिशत जमा करने पर शेष पचास प्रतिशत राशि माफ करने के निर्णय से, मेरी सरकार ने विगत दो वर्षों में लगभग पांच लाख पच्यासी हजार किसानों को सोलह करोड़ रूपये से अधिक की कर माफी प्रदान की है।

24. मेरी सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र को राज्य की प्रमुख शक्ति के रूप में पहचान और प्रतिष्ठा दिलाई है। देश में ऊर्जा के गंभीर संकट के बीच छत्तीसगढ़ रौशनी के द्वीप जैसा जगमगा रहा है। छत्तीसगढ़ देश का ऐसा अकेला राज्य है, जिसने अधिकारिक तौर पर 'जीरो पावर कट स्टेट' होने की घोषणा की है। राज्य शासन और संयुक्त उपक्रमों के सहयोग से नए बिजलीघर स्थापित किए जा रहे हैं। वहीं पारेषण तथा वितरण नेटवर्क में विस्तार से ओव्हर लोडिंग और लो–वोल्टेज की समस्या काफी हद तक समाप्त कर दी गई है।

25. मेरी सरकार द्वारा विद्युत विकास का लाभ जनकल्याणकारी योजनाओं के रूप में प्रदान किया जा रहा है। किसानों को सिंचाई पम्पों के कनेक्शन तत्काल प्रदान करने की स्थिति लाई गई है। पांच हार्स पॉवर तक के पम्पों पर निःशुल्क विद्युत सुविधा का दायरा बढ़ा दिया गया है। सभी वर्गों के पांच हार्स पॉवर तक सिंचाई पम्पधारी किसानों के लिए 'कृषक जीवन–ज्योति योजना' प्रारम्भ की गई है। इस योजना के तहत प्रति पम्प, वर्ष भर में छह हजार यूनिट विद्युत आपूर्ति निःशुल्क करने का निर्णय लिया गया है, जिस पर होने वाले लगभग एक सौ बत्तीस करोड़ रूपए का व्यय राज्य शासन वहन करेगा। केन्द्रीय विद्युत नियंत्रण अधिनियम–2003 के तहत गठित स्वायत्त–सांविधिक संस्था 'राज्य विद्युत नियामक आयोग' ने सिंचाई पम्पों पर फ्लैट रेट से विद्युत आपूर्ति की सुविधा 1 जुलाई,2009 से समाप्त करने का आदेश जारी किया था। इससे किसानों को तीन माह के बिजली बिल नई दर से मिले थे, जो कि फ्लैट रेट से अधिक थे। इस अंतर की राशि की प्रतिपूर्ति करके राज्य शासन द्वारा किसानों को राहत दी गई है।

26. मेरी सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से राज्य में उत्तम नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क 'स्वान' का कार्य सभी विकासखण्डों में पूर्ण हो गया है। इस नेटवर्क से न सिर्फ डेटा और वाईस का स्थानान्तरण होगा बल्कि सभी विकासखण्डों को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग की कनेक्टिविटी भी उपलब्ध होगी। छत्तीसगढ़ एक मात्र राज्य है, जिसने इस कार्य के लिए 'सैटेलाईट हब स्टेशन' बनाया है। शहरी चॉईस परियोजना की तरह नागरिक सेवाओं को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने के लिए राज्य में छह ग्राम समूहों के बीच एक 'सामान्य सेवा केन्द्र' प्रारम्भ किया जा रहा है। राज्य में अब–तक इस तरह के चौदह सौ से अधिक सेवा केन्द्र प्रारम्भ किए जा चुके हैं।

27. मेरी सरकार ने इस वर्ष दो हजार छब्बीस किलोमीटर लम्बाई के चौदह नए मार्गों को राज्य मार्ग घोषित किया है। पांच हजार दो सौ किलोमीटर लम्बाई के दो सौ बयालीस ग्रामीण मार्गों को मुख्य जिला मार्ग घोषित किया गया है। विगत वर्ष छिहत्तर वृहद पुलों और सात हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया गया । इस वर्ष उनतीस वृहद पुलों का काम पूर्ण हो चुका है और एक सौ अन्ठानबे वृहद पुलों का निर्माण प्रगति पर है। 'छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास परियोजना' के अंतर्गत करीब बारह सौ पचास किलोमीटर लम्बी बाइस पैकेज सड़कों में से करीब पांच सौ किलोमीटर लम्बी नौ पैकेज सड़कों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष सात सौ तिरसठ किलोमीटर लम्बी तेरह पैकेज सड़कों का कार्य प्रगति पर है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र योजना के तहत सात जिलों में सोलह सौ किलोमीटर की सड़कों को चिन्हित कर, इसमें से सात सौ किलोमीटर सड़कों के निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। दस राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य किया जा रहा है।

28. यातायात की रूकावटों को दूर करने के लिए राज्य में चार रेल्वे अंडर ब्रिज एवं ओव्हर ब्रिज गुढ़ियारी, आमापारा (रायपुर) तिफरा, दाधापारा (बिलासपुर) का निर्माण पूरा हो गया है। मोवा एवं टेकारी (रायपुर) डोंगरगढ़, उसलापुर एवं चकरभाटा (बिलासपुर) भिलाई–दुर्ग, अकलतरा, रायगढ़ में रेल्वे ओव्हर ब्रिज बनाए जा रहे हैं। आठ बायपास सड़कों का निर्माण प्रगति पर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अब–तक करीब इकतीस सौ सड़कें तथा उन्नीस हजार चार सौ से अधिक पुल–पुलिया बनाई जा चुकी है। एडीबी के सहयोग से सोलह सौ चौदह किलोमीटर सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है।

29. छत्तीसगढ़ की सीमाओं से जुड़े छह राज्यों में आवागमन सुविधाजनक बनाने के लिए मेरी सरकार ने इन राज्यों के साथ परिवहन समझौता किया है। अंतरराज्यीय परिवहन व्यवस्था को अधिक सुलभ और सुचारू बनाने के लिए परिवहन, वाणिज्यिक कर, खनिज, वन एवं कृषि उपज मंडी की एकीकृत जांच चौकियां स्थापित की जा रही हैं।

30. जनसुविधाओं और पर्यटन विकास के लिए मेरी सरकार ने घरेलू विमान सेवा शुरू करने की पहल की है। जिससे रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जशपुर, अंबिकापुर एवं जगदलपुर को वायुसेवा से जोड़ा

जा रहा है। अधोसंरचना विकास के तहत आगामी वर्षों में कबीरधाम, कोरिया, दंतेवाड़ा तथा बलरामपुर में नई हवाई पट्टियां बनाने की योजना है।

31. मेरी सरकार द्वारा नई 'औद्योगिक नीति 2009–14' लागू की गई है। इस नीति से औद्योगिक विकास का मापदण्ड जिले के स्थान पर विकास खण्ड को मान्य किया गया है। इससे औद्योगिक विकास सुनियोजित रूप से विकासखंड स्तर पर पहुंचाने में मदद मिलेगी। कमजोर तबकों, महिलाओं, विकलांगों, सेवानिवृत्त सैनिकों एवं नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्तियों को सामान्य वर्ग की अपेक्षा दस प्रतिशत अधिक अनुदान, छूट एवं रियायत दी गई है।

32. मेरी सरकार खनिजों के वेल्यू एडीशन के लिए राज्य में उद्योगों की स्थापना और खनिजधारित क्षेत्रों के विकास में निवेशकों को भागीदार बनाने की नीति पर अमल कर रही है। प्रदेश में स्थापित स्टील तथा स्पंज आयरन संयंत्रों को लौह अयस्क की आपूर्ति एनएमडीसी के माध्यम से सुनिश्चित कराई गई है। रावघाट लौह अयस्क प्रक्षेत्र पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के पक्ष में लौह अयस्क का बहुप्रतीक्षित खनिपट्टा स्वीकृत कर भिलाई स्टील प्लांट को आगामी पचास वर्षों के लिए लौह अयस्क की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

33. पंचायतों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए मेरी सरकार ने ग्राम पंचायतों में व्यावसायिक परिसर निर्माण की योजना संचालित की है, जिसके तहत तीन हजार या अधिक आबादी वाली चौवन ग्राम पंचायतों में प्रति ग्राम पंचायत इकतीस लाख रूपये के मान से निर्माण कराया जा रहा है। तेरह जिलों में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के माध्यम से दो सौ साठ करोड़ रूपए की लागत से अधोसंरचना विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। इस साल पचपन करोड़ रूपयों की लागत से ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना निर्माण के लगभग अठारह सौ कार्य कराए जा रहे हैं। ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व वाले स्थलों में भी बीस करोड़ रूपए की लागत से अधोसंरचना विकास के कार्य कराए जा रहे हैं।

34. यह हर्ष और गर्व का विषय है कि छत्तीसगढ़ को सैंतीसवें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी देने का प्रस्ताव भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा स्वीकार किया गया है। मेरी सरकार ने राज्य में खेलकूद का बेहतर वातावरण बनाने और युवाओं को कैरियर निर्माण में मदद के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय सेवा में लेने का निर्णय लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभ्यास और उचित प्रशिक्षण के लिए 'पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान योजना' के प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन की रणनीति अपनाई गई है।

35. छत्तीसगढ़ के शहरों को सुविधायुक्त ही नहीं, बल्कि नागरिकों के गौरव का प्रतीक बनाने की रणनीति के तहत मेरी सरकार ने बहुआयामी प्रयास किए हैं। राज्य प्रवर्तित योजनाओं सरोवर–धरोहर, पुष्पवाटिका, ज्ञानस्थली, उन्मुक्त खेल मैदान, प्रतीक्षा बस स्टैण्ड, सांस्कृतिक भवन, हाट बाजार, सार्वजनिक

प्रसाधन, मुक्तिधाम, मुख्यमंत्री स्वावलम्बन जैसी योजनाओं पर एक वर्ष में लगभग दो हजार सात सौ लाख रूपए का व्यय किया गया है। इसी तरह गौरव पथ, प्रवेश द्वार, उद्यान, सड़क, नाली, बिजली, पाइप लाईन विस्तार जैसे कार्यों पर इनक्यावन हजार दो सौ सत्तर लाख रूपए का अनुदान नगरीय निकायों को दिया गया। नागरिक स्वावलम्बन और जन सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं के क्रम में अन्नपूर्णा सामुदायिक सेवा केन्द्र और भागीरथी नल–जल योजनाएं इसी वर्ष लागू की गई है।

36. मेरी सरकार ने गांवों में रोजगारपरक योजनाओं को कारगर ढंग से अमल में लाया है। नवा अंजोर परियोजना में लगभग इक्कीस हजार समहित समूहों के जरिए एक लाख से अधिक लोगों को स्व–रोजगार उपलब्ध कराया गया है। अब सभी विकासखंडों में विपणन केन्द्र की स्थापना की जा रही है। रोजगार गारंटी योजना के तहत चौंतीस लाख इकहत्तर हजार परिवारों का पंजीयन कर उन्हें रोजगार कार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। पचपन लाख चौंतीस हजार श्रमिकों के खाते बैंक और पोस्ट ऑफिस में खोले गए हैं। इस वर्ष मांग के आधार पर करीब सोलह लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। हर्ष का विषय है कि बिलासपुर और कोरिया जिलों को भारत सरकार ने योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु पुरस्कृत किया है।

37. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत इस वर्ष बत्तीस हजार से अधिक हितग्राहियों को लगभग एक सौ पन्द्रह करोड़ रूपए का ऋण एवं अनुदान दिया गया है। बीपीएल परिवारों के लिए ग्यारह जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान प्रारम्भ किए गए हैं। प्रत्येक जिले में तीन–तीन ग्रामीण हाट का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को बीमा सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने के लिए 'आम आदमी बीमा योजना' एक फरवरी 2009 से प्रारम्भ की गई है, जिसके तहत लगभग तीन लाख चालीस हजार परिवारों को लाभान्वित करने का कार्य प्रक्रिया में है।

38. मेरी सरकार ने परम्परागत रोजगार के साधनों को नई तकनीक और विपणन की सुविधाओं से संवारा है। हाथकरघा उद्योग से जुड़े बावन हजार बुनकर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। लोफंदी जिला बिलासपुर एवं भंवरपुर जिला महासमुन्द में नए क्लस्टर प्रस्तावित हैं। कृमिपालक हितग्राहियों के लिए करीब एक हजार बीस हेक्टेयर रकबे में चॉकी क्षेत्र संधारण किया जाएगा, जिससे कोसा उत्पादन में वृद्धि होगी। टसर रेशम संबंधित विभिन्न योजनाओं में उन्यासी हजार हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। इंटीग्रेटेड एक्सीलेंस प्रोजेक्ट, बांस शिल्प परियोजना, कम्प्यूटर एडेड डिजाइन सेन्टर, छत्तीसगढ़ हाट, नवीन शबरी एम्पोरियम, ग्लेजिंग यूनिट, टीसीपीसी बिलासपुर आदि केन्द्रों की स्थापना से लगभग छत्तीस हजार शिल्पियों को बेहतर आय के अवसर प्रदान करने की योजना है।

39. मेरी सरकार ने प्रदेश में स्थापित हो रही औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने की रणनीति अपनाई है। इसके लिए यथोचित शिक्षण तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। अंबिकापुर

में इंजीनियरिंग कॉलेज तथा रायपुर में आईआईएम की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, जशपुर, कोरिया, दंतोवाड़ा, गरियाबंद, रायपुर में पॉलीटेक्निक शीघ्र प्रारम्भ किए जाएंगे।

40. मेरी सरकार ने प्रदेश में बेहतर राजस्व प्रबंधन एवं जनसुविधा के लिए पटवारी हल्कों का पुनर्गठन किया है। दो ग्राम पंचायतों पर एक पटवारी हल्के के गठन का निर्णय लिया गया है। इसके कारण पटवारी हल्कों की कुल संख्या तीन हजार छियासी से बढ़कर चार हजार आठ सौ तिरालीस हो गई है। तद्नुसार नए पदों पर भर्ती की जा रही है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, धमतरी, जगदलपुर एवं कोरबा जैसे दस नगरों में नजूल सर्वे का कार्य इसरो की मदद से कराया जाएगा।

41. मेरी सरकार राज्य की सांस्कृतिक विरासतों और धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के हर संभव प्रयास कर रही है। सिरपुर को विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने के कार्य में प्रगति हुई है। यूनेस्को के एक विशेषज्ञ दल द्वारा स्थल का भ्रमण किया गया है। पुरातात्विक संपदा से परिपूर्ण राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय महत्व के अनेक स्थल चिन्हित किए गए हैं। यहां पर तीन वर्षों में सौ करोड़ रूपये की लागत से पर्यटन अधोसंरचना का विकास किया जाएगा । इक्कीस स्थानों पर पर्यटक विश्राम गृह (मोटल) निर्माणाधीन हैं। जगदलपुर में टूरिस्ट सुविधा केन्द्र एवं हर्बल रिसोर्ट का निर्माण प्रगति पर है।

42. मेरी सरकार ने न्याय को सर्वसुलभ बनाने के लिए अधोसंरचना और नवीन पदों के सृजन का काम प्राथमिकता से किया है। पारिवारिक मामलों के त्वरित निराकरण के लिए उन्नीस कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना की गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के इकतीस फास्ट ट्रेक कोर्ट की अवधि बढ़ाई गई है। सोलह जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए पूर्णकालिक सचिव के पद निर्मित किए गए हैं। इसी तरह राज्य के पच्चीस स्थानों पर सिविल न्यायाधीश वर्ग दो के पच्चीस पद सहित अन्य स्थापनाओं के लिए तीन सौ उन्यासी पद निर्मित किए गए हैं।

43. राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिक पुलिस बल एवं भौतिक संसाधनों की आवश्यकता पूरा करने के लिए मेरी सरकार लगातार प्रयासरत है। विगत वर्ष सीधी भर्ती से छह हजार सात सौ से अधिक आरक्षकों की भर्ती की गई। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तेइस नए थानों की मंजूरी, चार पुलिस चौकियों का थानों में उन्नयन किया गया। इसके लिए करीब उन्नीस सौ नए पद स्वीकृत किए गए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के जवानों एवं अधिकारियों के मनोबल को ऊंचा बनाए रखने हेतु नक्सल ड्यूटी भत्ता प्रदान करने का दायरा बढ़ाया गया है। पांचवी वाहिनी जगदलपुर एवं पीटीएस राजनांदगांव एवं पुलिस अकादमी चंदखुरी में काउन्टर इन्सरजेंसी एण्ड एन्टी टेररिस्ट स्कूल की स्थापना की जा रही है। सीटीजेडब्ल्यू कॉलेज, कांकेर के लिए भी करीब डेढ़ सौ नए पद स्वीकृत किए गए हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस को भवनों के निर्माण एवं मरम्मत आदि के लिए पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। थानों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के कार्यालयों को आपस में जोड़ने हेतु 'क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्ट्मस योजना' लागू की जा रही है।

44. प्रदेश की जेलों को मजबूत बनाने और वहां सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण का कार्य किया जाएगा। जेलों में वॉच टॉवर निर्माण, जैमर, हाईमास्क लाइट, सीसीटीवी आदि उपलब्ध कराया जा रहा है। छह जिलों में वीडियो कॉन्फरेन्सिंग प्रणाली प्रदान कर इसके माध्यम से न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई की सुविधा दी गई है।

45. मेरी सरकार के सतत् प्रयासों से अनेक क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ देश के अव्वल राज्यों में गिना जाने लगा है। सिर्फ नौ साल पहले भारत के मानचित्र में नए राज्य के रूप में उदित हुए इस राज्य में विकास के अवसरों और विकास के वातावरण पर दुनिया ने अगर विश्वास जताया है, तो उसका एक बड़ा कारण आप सबकी चेतना, भागीदारी और विकास के एजेण्डे पर सहमति की मुहर लगाना भी है। छत्तीसगढ़ में आम जनता की खुशहाली के लिए आपका एकमत होना ही राज्य में समरस विकास के नए कीर्तिमान गढ़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबके सहयोग से छत्तीसगढ़ लोकतंत्र की चुनौतियों और जनकल्याणकारी राज्य की कसौटियों पर खरा उतरेगा।

46. नए साल में राज्य को नक्सली हिंसा से मुक्ति मिले, प्रभावित क्षेत्रों में नवनिर्माण हो, समूचे राज्य में खुशहाली की नई चमक आए, नव वर्ष पर इन्हीं शुभकामनाओं सहित।

जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़